Sanskritik aur Samajik Anusandhan
www.shodhjournal.com
ISSN: 2582-5852
Received: 26-08-2022, Accepted: 12-09-2022, Published: 28-09-2022
Volume 3, Issue 2, 2022, Page No. 7-9

नवभारत के निर्माता– डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

कुमार संजय झा[1], मनोज कुमार[2]
[1] निदेशक, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राँची, झारखंड, भारत
[2] परियोजना सहायक, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली, भारत

सारांश
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान देशभक्त, शिक्षाविद्, सांसद, राजनेता, मानवतावादी और सबसे बढ़कर, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रचारक थे। उन्होंने भारत के नवनिर्माण और पुनिर्माण के लिए संघर्ष किया। उनको लगा कि भारत का पुनर्निर्माण भारतीय मर्यादा और संस्कृति पर आधारित होकर ही संभव हो पाएगा। आने वाले वर्षों में आजाद भारत की नीति, लोकनीति, राष्ट्रीय नीति को संस्कृति के आधार पर ही निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए उस सोच से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। उन्होंने आजाद भारत के प्रथम केन्द्रीय उद्योग आपूर्ति मंत्री के नाते आजाद भारत में औद्योगिक नींव रखी। उनके व्यक्तित्व का हर पक्ष असाधारण और अद्भुत है। इस दिशा में उन्होंने भारतीयकरण का प्रयोग किया। सिंचाई, स्टील प्रोडक्शन, फ़र्टिलाइज़र प्रोडक्शन, एमएसएमई, कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी, हर जगह हर डायमेंशन में उन्होंने अपना अवदान रखा। कॉटेज एम्पोरियम के उद्योग की शुरूआत उन्होंने ही की थी। खादी की बात करें तो विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, उन्होंने शुरू किया। प्रतिरक्षा उद्योग के भारतीयकरण की बात अगर करते हैं तो इसकी नींव भी डॉ. मुखर्जी ने ही रखी थी। सिंचाई, एमएसएमई जैसे उपादानों को खड़ा कर उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास किया था।

मूल शब्दः राष्ट्र, मानवतावादी, शिक्षा नीति, अखंडता

प्रस्तावना
स्वतंत्र संप्रभु भारत के संस्थापको में से एक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान देशभक्त, शिक्षाविद्, सांसद, राजनेता, मानवतावादी और सबसे बढ़कर, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रचारक थे। 6 जुलाई, 1901 को कलकत्ता में जन्में श्यामा प्रसाद को अपने पिता, सर आशुतोष मुखर्जी से उत्कृष्ट राष्ट्रवाद और निडरता की एक समृद्ध परंपरा विरासत में मिली। उनकी मां श्रीमती जोगमाया देवी, एक धर्मनिष्ठ हिंदू महिला थीं, जो पूरी तरह से अपने पति, परिवार और धर्म के प्रति समर्पित थीं। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र की ऐसी संतान एवं विभूति थे, जो देश की एकता एवं अखंडता हेतु तत्पर रहे। उन्होंने देश की आजादी से पहले न केवल देश के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्रता के बाद भी देश की एकजुटता के पक्षधर थे। एक ही देश में दो झंडे और दो प्रधान उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की। दरअसल, उस समय जम्मू–कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था और वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। लेकिन डॉ. मुखर्जी जम्मू–कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जोरदार नारा भी बुलंद किया कि 'एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।'

सबसे कम उम्र के कुलपति
1923 में उनके पिता की मृत्यु हुई, जिन्हें वे अपने छात्र जीवन से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय चलाने में सहायता कर रहे थे, इस घटना ने उन्हें एक छात्र रहते हुए भी शैक्षिक क्षेत्र में ला दिया। उन्हें अपने कुलपति पिता की शैक्षिक योजनाओं और नीतियों में सबसे करीबी अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। वे 1924 में विश्वविद्यालय सीनेट और सिंडिकेट के लिए चुने गए और बंगाल विधान परिषद में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया। 1930 में जब कांग्रेस ने विधायिकाओं का बहिष्कार करने का फैसला किया, तो उन्होंने विधान परिषद में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जल्द ही अपने विश्वविद्यालय के हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में परिषद में फिर से प्रवेश किया। हालाँकि, उनका मुख्य व्यवसाय शिक्षा के कारण सेवा करना जारी रहा।[1] 1934 में, श्यामा प्रसाद कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, जिसने उन्हें अपने लोगों की शिक्षा के संबंध में अपने लक्ष्य और आदर्शों को व्यवहार में लाने का अवसर दिया। उनके कुलपति रहते ही रवींद्र नाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में अपना दीक्षांत भाषण दिया, जिसने बंगाली और अन्य भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी श्रेष्ठता के युग के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया।

एक राष्ट्रवादी के रूप में
1935 के भारत सरकार अधिनियम और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनावों ने देश की स्थिति को एक नया मोड़ दिया। उन्हें फिर से विश्वविद्यालय निर्वाचन क्षेत्र से बंगाल विधानमंडल में लौटा दिया गया, जिससे उन्हें बहुत करीब से प्रांतीय स्वायत्तता के कामकाज का अध्ययन करने का अवसर मिला। 250 सदस्यों वाले सदन में हिंदुओं को केवल 80 सीटें दी गई थीं, जिसके लिए ज्यादातर कांग्रेसी वापस आ गए थे। बाकी मुसलमानों और ब्रिटिश हितों के बीच बंटे हुए थे।

मुस्लिम सदस्यों को 'मुस्लिम लीग' और 'कृषक प्रजा पार्टी' के बीच विभाजित किया गया था। अगर कांग्रेस पार्टी ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ गठबंधन किया होता, तो बंगाल को एक गैर–मुस्लिम लीग की स्थिर सरकार मिल सकती थी। विधायिका 80011 के अंदर और बाहर की स्थिति को संभालने वाली कांग्रेस ने उन्हें अपनी नीतियों और राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए उकसाया।

अपने मंत्रालय के गठन पर, मुस्लिम लीग ने शैक्षिक ढांचे पर हमला करने का फैसला किया, जिसे उनके पिता और उन्होंने खुद इतनी मेहनत से बनाया था। स्पष्ट और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित की कीमत पर भी मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति उनके जन्मजात राष्ट्रवाद के प्रतिकूल थी, जिसने उनमें कार्य करने वाले व्यक्ति को जगाया। मुस्लिम लीग को सत्ता का एक सुरक्षित मंत्र देने की अपनी नीति को बदलने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को मनाने में विफल रहने के बाद, उन्होंने मुस्लिम लीग मंत्रालय को गिराने के लिए अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने विधानमंडल में सभी गैर–कांग्रेसी हिंदू ताकतों को एक साथ इकट्ठा किया और फजल–उल–हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी के साथ प्रगतिशील गठबंधन का गठन किया, (गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में), इसने उनकी स्थिति को एक व्यावहारिक के रूप में तथा दूरदर्शी राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित किया।

इसी अवधि के दौरान, वीर सावरकर के प्रभाव में, वे हिंदू महासभा में शामिल हो गए और राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने के लिए कार्य किया। इसके तुरंत बाद, 1939 में वे इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता को हिंदू महासभा के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में घोषित किया। उनके हिंदू महासभा में शामिल होने का महात्मा गांधी ने स्वागत किया, जिन्होंने स्वीकार किया कि ष्मालवीय जी के बाद हिंदुओं का नेतृत्व करने के लिए किसी की आवश्यकता थी" ।[2] गांधीजी श्यामा प्रसाद के व्यापक और पूर्ण राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुखर्जी के संदर्भ में कहा कि "पटेल एक कांग्रेसी है जिसका हृदय हिंदू का है। तुम एक हिंदुभाई हो जिसका हृदय कांग्रेस का है।"[3] 1943 में, श्यामा प्रसाद ने पुलिस और सामान्य प्रशासन के मामलों के मंत्री स्तर के निर्वहन में राज्यपाल और नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए बंगाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और बहुत अधिक विज्ञापित प्रांतीय स्वायत्तता को एक मात्र दिखावा बताया। जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद को लात मारी, उससे यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई भी प्रलोभन कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं कर सकता था। लॉर्ड अनलिथगो के साथ उनका पत्राचार, जिसमें उन्होंने उनसे हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने, लोगों पर भरोसा करने और जापानी खतरे को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय रक्षा बल के गठन की अनुमति देने का आग्रह किया[4], राष्ट्रीय कारणों में उनके प्रेरक कौशल का पर्याप्त प्रमाण था।

उन्होंने 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान में इसके हिंदू–बहुल क्षेत्रों को शामिल करने से रोका जा सके। उन्होंने 1947 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शहीद सुहरावर्दी द्वारा बनाई गई एक संयुक्त लेकिन स्वतंत्र बंगाल के लिए एक असफल बोली का भी विरोध किया। अगर डॉ. मुख़र्जी नहीं रहते तो पूरा बंगाल और पंजाब पाकिस्तान होता। उन्होंने असम को भारत का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बंगाल एक अद्वितीय उदाहरण है कि कैसे भारतवर्ष की एकता और अखंडता उनके अंदर आत्मसात थे और उसके लिए वो किसी सीमा तक जा सकते थे।

धर्म पर आधारित राष्ट्र विभाजन की योजना बनी थी, उसके अनुसार उत्तर भारत के पूर्वी और पश्चिमी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल करना था। डॉ. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी ने पूरे बंगाल के पूर्वी पाकिस्तान बन जाने की स्थिति को देख लिया। बंगाल में हिन्दू जनसंख्या कम नहीं थी, किन्तु बंगाल को एक साथ देखने पर मुस्लिम बहुलता आ सकती थी। बंगाल के अंदर ही पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में यदि क्रमशः मुस्लिम बहुल और हिन्दू बहुल के दो क्षेत्र बन जाये तो कोलकाता के साथ पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा होगा, यह डॉ. श्यामा की राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की मूल भावना ने समझ लिया था। सम्मलेन बुलाकर जनमानस में जागरूकता लाना, राष्ट्रभक्तों की फ़ौज खड़ी करके फिर शीर्ष नेतृत्व और गाँधी जी के समक्ष प्रस्ताव रखना, ये उनके कुशल प्रबंधन के उदाहरण थे कि धुर विरोधियों ने भी राष्ट्र की एकता के उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हीं के कारण कोलकाता हमारे साथ है।

मानवतावादी के रूप में

1943 के बंगाल के अकाल ने डॉ. श्यामा प्रसाद के मानवतावादी रूप को सबसे आगे ला दिया, जिसे बंगाल के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं, भले ही उनमें से कुछ को उनकी राजनीति पसंद न आई हो। बंगाल में संकट की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने और अकाल से पीड़ित लोगों के लिए बड़े पैमाने पर राहत की व्यवस्था करने के लिए, उन्होंने प्रमुख राजनेताओं, व्यापारियों और परोपकारी लोगों को जरूरतमंदों और संकटग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के तरीके और साधन विकसित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके जवाब में बंगाल राहत समिति का गठन किया गया और हिंदू महासभा राहत समिति का भी गठन किया गया। डॉ. श्यामा प्रसाद दोनों संगठनों के पीछे गतिशील आत्मा थे। निधि के लिए उनकी अपील को पूरे देश से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और बड़ी मात्रा में धन आना शुरू हो गया। यह मुख्य रूप से उनके कारण था कि पूरा देश राहत प्रदान करने में एक आदमी की तरह उठ खड़ा हुआ, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई।[5]

उनकी सहानुभूति केवल मौखिक नहीं थी, उन्होंने ऐसे सुझाव दिए जो व्यावहारिक थे और जो उनके सच्चे मानवीय हृदय को प्रकट करते थे। स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने एक बार विभाजन में सुझाव दिया: "हमें अब 40 रुपये प्रति दिन मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके बाद लोक सभा के सदस्यों का भत्ता क्या होगा। आइए हम प्रति 10 रुपये की स्वैच्छिक कटौती के लिए सहमत हों। आइए हम इस राशि को उन घरों को खोलने के उद्देश्य से, जहां इन महिलाओं और बच्चों (अकाल प्रभावित क्षेत्रों के) को रखा जा सकता है और खिलाया जा सकता है।"[6]

जनसंघ के संस्थापक के रूप में

कैबिनेट छोड़ने के बाद सरना प्रसाद ने अपनी ऊर्जा एक राजनीतिक मंच बनाने पर केंद्रित की, जिसके माध्यम से वे जिस विचारधारा और नीतियों के लिए खड़े थे। प्रक्षेपित किया जा सकता था। उन्होंने हिंदू महासभा को पहले ही छोड़ दिया था, जिसने जाति और पंथ के बावजूद "भारतीयों" के लिए अपना दरवाजा खोलने के उनके सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

श्यामा प्रसाद ने विपक्ष में नेतृत्व एक नए राष्ट्र को आकार देने का फैसला किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय जनसंघ को औपचारिक रूप से अक्टूबर 1950 में शुरू किया गया था। उन्हें नए संगठन का नेतृत्व करने के लिए इसके पहले अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने जनसंघ को देश में राष्ट्रवादी ताकतों के अगुआ के रूप में देखा और वे चाहते थे कि यह इतना व्यापक हो कि प्रभावी राजनीतिक संगठन में समझने और समेकित करने में सक्षम हो।[7] नई पार्टी की आवश्यकता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा था: "कांग्रेस के शासन में तानाशाही के प्रकट होने का एक मुख्य कारण हम की अनुपस्थिति है"[8] श्यामा प्रसाद ने अपना शेष जीवन उस पार्टी के विकल्प के रूप में इस संगठन के निर्माण में बिताया जो उस समय सत्ता में थी।

आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में

21 अक्टूबर, 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने भारत के नवनिर्माण और पुनिर्माण के लिए संघर्ष किया। उनको लगा कि भारत का पुनर्निर्माण भारतीय मर्यादा और संस्कृति पर आधारित होकर ही संभव हो पाएगा। आने वाले वर्षों में आजाद भारत की नीति, लोकनीति, राष्ट्रीय नीति को संस्कृति के आधार पर ही निर्धारित करना पड़ेगा। इसलिए उस सोच से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। उन्होंने आजाद भारत के प्रथम केन्द्रीय उद्योग आपूर्ति मंत्री के नाते आजाद भारत में औद्योगिक नींव रखी। उनके व्यक्तित्व का हर पक्ष असाधारण और अद्‌भुत है। इस दिशा में उन्होंने भारतीयकरण का प्रयोग किया। सिंचाई, स्टील प्रोडक्शन, फ़र्टिलाइज़र प्रोडक्शन, एमएसएमई, कॉटेज इंडस्ट्रीज, खादी, हर जगह हर डायमेंशन में उन्होंने अपना अवदान रखा। कॉटेज एम्पोरियम के उद्योग की शुरूआत उन्होंने ही की थी। खादी की बात करें तो विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, उन्होंने शुरू किया। प्रतिरक्षा उद्योग के भारतीयकरण की बात अगर करते हैं तो इसकी नींव भी डॉ. मुखर्जी ने ही रखी थी। सिंचाई, एमएसएमई जैसे उपादानों को खड़ा कर उन्होंने भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का प्रयास किया था। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में रास्ता प्रारंभ करने वाले पहले पुरूष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? नए भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए? इसके बारे में उन्होंने अपने कई दीक्षांत समारोहों के भाषण में रखा था। उन्होंने जनसंघ का गठन कर और राजनीतिक यात्रा प्रारंभ कर इस देश में नई सोच की आधारशिला रखी थी। जनसंघ के प्रथम अधिवेशन के उनके अध्यक्षीय भाषण में 'भारतीय संस्कृति' और 'भारतीय मर्यादा' ये दो शब्द बार–बार आए हैं।

अंत में उनके चिंतन का पहलू जो बार बार उनके भाषणों में मुखरित होता था, वह है एकता और एकात्मता। उनके अपने विचार के केन्द्र में इन तत्वों को रखा था और अपने जीवन का मूल्य भी इन्हीं तत्वों पर निर्धारित किया था। कश्मीर की यात्रा से पहले उन्होंने डेढ़ महीनों तक पंडित जवाहर लाल नेहरू एवं शेख अब्दुल्लाह को कई पत्र लिखे। यही नहीं उन्होंने अपने कई संसदीय भाषणों में कहा था कि कृपया केवल चार करोड़ मुसलमानों को अलग से कोई प्रिविलेज नहीं दी जाए। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए घातक साबित होगा और देश की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा करेगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले राजनेता हैं, जिन्होंने नेहरू के या कांग्रेस के प्रवल बहुमत के सामने विपक्ष की एकता की नींव डाली और जो उसका नाम रखा वो भी नेशलन डेमोक्रैटिक एलायंस था और उसका नेतृत्व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। उनके नेतृत्व से नेहरू की नींद हराम हो गयी। इसलिए डॉ. मुखर्जी को हमेशा के लिए नींद में सुला दिया गया और उसका रहस्य शायद कभी उजागर नहीं होगा। उस डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मैं नमन करता हूं।

संदर्भ सूची

1. Eminent Parliamentarians Monograph Series; Dr. Syama Prasad Mookerjee Lok Sabha Secretariat New Delhi '1990
2. दत्त, हरीश शर्मा; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी; डायमंड बुक्स; पृष्ठ 45
3. दत्त, हरीश शमा; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी; डायमंड बुक्स; पृष्ठ 45
4. Eminent Parliamentarians Monograph Series; Dr. Syama Prasad Mookerjee Lok Sabha Secretariat New Delhi '1990
5. Eminent Parliamentarians Monograph Series; Dr. Syama Prasad Mookerjee Lok Sabha Secretariat New Delhi '1990
6. Eminent Parliamentarians Monograph Series; Dr. Syama Prasad Mookerjee Lok Sabha Secretariat New Delhi '1990
7. Eminent Parliamentarians Monograph Series; Dr. Syama Prasad Mookerjee Lok Sabha Secretariat New Delhi '1990
8. दत्त, हरीश शर्मा; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी; डायमंड बुक्स; पृष्ठ 45